दैनिक भास्कर
जयपुर 18-08-2025

चुनावी शुद्धता पर आर-पार

सात दिन में हलफनामा दें या माफी मांगें... तीसरा विकल्प नहीं: आयोग

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में विपक्ष के गड़बड़ी के आरोपों के बीच निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस (पीसी) कर जवाब दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने 85 मिनट की पीसी में कहा, 'या तो हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा विकल्प नहीं है। सात दिन में हलफनामा नहीं मिला, तो मतलब सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र का वोटर नहीं है और शिकायत कराना चाहता है तो शपथ लेकर ही ऐसा कर सकता है।' नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 31 जुलाई को कर्नाटक के महादेवपुरा सीट में एक लाख वोट चोरी होने का आरोप लगाया था। ज्ञानेश कुमार ने कहा, क्या बिना शपथपत्र हम 1.5 लाख वोटर्स को नोटिस जारी कर दें? आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। शेष | पेज 4

सीईसी और निर्वाचन आयुक्त

हमारे लिए न कोई पक्ष, न कोई विपक्ष, सब समकक्ष

- सीईसी ने कहा, 'वोट चोरी' जैसे शब्द संविधान का अपमान नहीं तो क्या?
- सुप्रीम कोर्ट ने मशीन रीडेबल सूची को वोटर्स की निजता का हनन कहा है।
- क्या किसी की माताओं, बहुओं, बेटी की वोटिंग का सीसीटीवी वीडियो आयोग को साझा करनी चाहिए?
- आयोग के लिए न कोई विपक्ष है, न पक्ष, सब समकक्ष हैं। आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति हो रही है।
- सूरज पूर्व से निकलता है। किसी के कहने से दिशा नहीं बदलती।

65 लाख नाम जारी... सीईसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 56 घंटे के अंदर बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए 65 लाख नाम वेबसाइट पर जारी किए गए।

आयोग ने जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया, फुटेज देने में बहाना बना रहे: राहुल

एम. रियाज हाशमी | सासाराम

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बिहार के रोहतास से 1300 किमी. लंबी 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की। इससे पहले उन्होंने कहा, 'आयोग भाजपा के साथ मिलकर चुनाव चोरी कर रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव चुराए जा रहे हैं। गरीब की ताकत वोट है। यही उसकी आवाज, उसकी पहचान है। वही ताकत छीनी जा रही है। हम हर कीमत पर वोट चोरी रोकेंगे।' यात्रा से पहले सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राजद प्रमुख लालू प्रसाद सहित महागठबंधन के प्रमुख नेता मौजूद रहे। सीईसी की पीसी के बाद राहुल ने कहा, आयोग ने जिंदा लोगों को मरा घोषित कर दिया। मशीन-रीडेबल वोटर रोल देने से मना कर दिया। आयोग सीसीटीवी फुटेज न देने के बहाने बना रहा है। पहले वोट चोरी दबे पांव की, अब एसआईआर के नाम पर खुलेआम की जा रही है। शेष | पेज 4

यात्रा में राहुल और तेजस्वी

क्या भाजपा के नेताओं से भी हलफनामा मांगा गया?

- राहुल ने कहा, मेरी पीसी के बाद मुझसे हलफनामा मांगा गया। भाजपा नेताओं ने भी ऐसे आरोप लगाए, क्या उसने कोई हलफनामा मांगा गया?
- संघ और भाजपा संविधान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई डॉ. आंबेडकर के संविधान की है।
- **सपा प्रमुख अखिलेश यादव** ने कहा, हमने आयोग को हलफनामे दिए, पावती भी है। अब आयोग शपथपत्र दे कि जो डिजिटल रसीद हमें दी है वो सही है या नहीं?

तेजस्वी बोले, चोरी नहीं अब डकैती... बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा वोट चोरी नहीं, आयोग के साथ मिलकर डकैती करने लगी है।

दैनिक नवज्योति Jaipur City - 18 Aug 2025 - Page 2

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस

प्रजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं, सात दिन में हलफनामा पेश करें या माफी मांगें : ज्ञानेश

एजेंसी/नई दिल्ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में विपक्ष के वोट चोरी और चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगे। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। एक पार्टी के साथ साठगांठ के आरोपों पर सीईसी ने कहा- हमारे लिए न कोई पक्ष और न विपक्ष है। सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन न हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। सीईसी ने कहा- कुछ मतदाताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे आरोपों

से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता है। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल, राहुल ने 7 अगस्त को ईसी पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था, 'वोट चोरी हो रहे हैं। हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग चोरी में शामिल है। वे भाजपा के लिए ऐसा कर रहे हैं।'

आयोग का पक्षपात बेनकाब: जयराम

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ नाकाम ही नहीं, बल्कि पक्षपात में भी पूरी तरह बेनकाब हो गया है। उन्होंने पूछा कि क्या आयोग बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के आदेश को सही मायने में लागू करेगा? जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने जो बातें कहीं, वे आयोग के अपने आंकड़ों पर आधारित हैं। सीईसी ने राहुल गांधी के सवालों का कोई सार्थक जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग का यह दावा कि वह सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई भेदभाव नहीं करता, मजाक जैसा है।

अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगते: राहुल

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा कि जो बात वो कह रहे हैं वही बात तो अनुराग ठाकुर ने भी कही है। फिर चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांग रहा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए और हमारा गठबंधन जीत गया। चार महीने बाद, विधानसभा चुनाव हुए और उसी महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन ने जीत हासिल कर ली और हमारा गठबंधन दिखाई ही नहीं दिया। गायब हो गया। जब हमने जांच की तो पता चला कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के बाद चार महीनों में जादुई तरीके से एक करोड़ नए मतदाता बना दिए। जहां भी नए मतदाता आए, वहां भाजपा जीत गई। हमारे वोट कम नहीं हुए।

दैनिक नवज्योति Jaipur City - 18 Aug 2025 - Page 2

बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू

50% आरक्षण सीमा हटाएंगे, असली जाति जनगणना कराएंगे: राहुल

एजेंसी/पटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा केवल दबाव में की है, लेकिन न तो यह असली जाति जनगणना कराएगी और न ही आरक्षण पर लगे 50% की सीमा को हटाएगी। बिहार के सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा की शुरूआत करते हुए राहुल गांधी ने यह बात कही। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, हमने संसद में कहा था कि हमें जाति जनगणना चाहिए और आरक्षण पर 50% की सीमा की दीवार को खत्म किया जाना चाहिए। मैंने यह बात प्रधानमंत्री मोदी के सामने कही थी। राहुल गांधी ने दोहराया कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक देश भर में जाति जनगणना कराएगा और आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अप्रैल में घोषणा की थी कि अगली जनगणना में जातिगत विवरण शामिल किया जाएगा, जो आजादी के बाद पहली बार होगा।

20 जिलों से निकलेगी यात्रा

वोटर अधिकार यात्रा बिहार के 20 से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी, जिसका उद्देश्य कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस के अभियान को तेज करना है।

'लागल-लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकता चले: लालू

बिहार के सासाराम में वोट अधिकार रैली की जनसभा को संबोधित करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने कहा- चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, हमारी पार्टी को जिताइए। आखिर में उन्होंने भोजपुरी गीत की लाइन कही- 'लागल-लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकता चले। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद।

दैनिक नवज्योति
Jaipur City - 18 Aug 2025 - Pa

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कमजोरः गहलोत

ब्यूरो/ नवज्योति,जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक्स पर टिप्पणी करते हुए लिखा-खोदा

पहाड़ निकली चुहिया वाली स्थिति रही। चुनाव आयोग राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी जवाब नहीं दे पाया। यह मुद्दा देश के गांव-गांव तक पहुंच गया है। देशवासी उम्मीद कर रहे थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त उन सभी तथ्यों का सिलसिलेवार जवाब देंगे, जो राहुल ने उठाए थे, हालांकि अपने हल्के तर्कों से चुनाव आयोग ने निराश किया है। उन्होंने आगे लिखा- यह भी आश्चर्यजनक है कि चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आज का दिन चुना जब राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया और तमाम पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की भावना है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना ही नहीं, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। आज चुनाव आयोग के पास में मौका था कि वह अपनी छवि को सही कर पाता पर उसने यह मौका गंवा दिया।

पंजाब केसरी
MON,18 AUGUST 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

सासाराम : 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते राहुल गांधी व तेजस्वी यादव।

'चुनाव चोरी' नहीं होने देंगे : राहुल

'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत

सासाराम, 17 अगस्त (एजैंसी): लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कथित वोट चोरी के खिलाफ यहां से "वोटर आधिकार यात्रा" शुरू की। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए बिहार में चुनाव चोरी करने की साजिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे सफल नहीं होने देगा। उन्होंने दावा किया कि अब सबको पता चल गया है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर पूरे देश में वोट की चोरी कर रहा है।

यात्रा की शुरुआत से पहले सासाराम के बिआडा मैदान में I.N.D.I.A. के नेताओं की एक सभा का (शेष पृष्ठ 13 कालम 3 पर)

संबंधित खबर पेज- 12

निर्वाचन आयुक्तों को बचाने के लिए 2023 में बदला गया कानून

औरंगाबाद: राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग के संवाददाता सम्मेलन के बाद आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में कानून में बदलाव करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई के दायरे से मुक्त किया गया। उन्होंने औरंगाबाद के रमेश चौक पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कहा, "मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सीसीटीवी फुटेज देने का कानून बनाया, फिर इसे बदला क्यों? निर्वाचन आयुक्त पर कहीं मामला दर्ज नहीं हो सकता।" उन्होंने आरोप लगाया

(शेष पृष्ठ 13 कालम 3 पर)

पंजाब केसरी
MON,18 AUGUST 202
EDITION: JAIPUR, P

'चुनाव आयोग नहीं दे पाया राहुल के मुद्दों का जवाब'

जयपुर,17 अगस्त (ब्यूरो): पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश की निगाहें आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थीं पर

यह खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली स्थिति रही, चुनाव आयोग लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए मुद्दों पर प्रभावी जवाब नहीं दे पाया। यह मुद्दा देश के गांव-गांव तक पहुंच गया है। देशवासी उम्मीद कर रहे थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त उन सभी तथ्यों का सिलसिलेवार जवाब देंगे जो राहुल गांधी ने उठाए थे, हालांकि अपने हल्के तर्कों से चुनाव आयोग ने निराश किया है एवं वो एक भी मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया।

सूचि में हेराफेरी का आरोप लगाने वाले 7 दिन में सबूत दें- चुनाव आयोग

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हेराफेरी के संगीन आरोप पर बिना हलफनामे कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती

नयी दिल्ली, 17 अगस्त। चुनाव आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों की मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर शपथ पत्र के साथ सात दिन के अंदर सबूत पेश करने, अन्यथा देश से माफी मांगने के लिए कहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को यहां विशेष रूप से आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कोई किसी सूची में डेढ़ लाख मतदाताओं के नाम फर्जी होने का आरोप लगा दे, तो क्या आयोग बिना हलफनामे के उनको नोटिस जारी कर देगा और उन्हें उप मंडलीय अधिकारी (एसडीएम) के दरवाजे पर चक्कर लगाने के लिए विवश करेगा।

उन्होंने कांग्रेस नेता गांधी द्वारा कर्नाटक और महाराष्ट्र की सूचियों में गड़बड़ी के लगाये गये आरोपों को लेकर पूछे गये सवालों का जवाब देते हुए कहा,

> ■ चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई किसी सूची में डेढ़ लाख मतदाता फर्जी होने का आरोप लगा दे, तो क्या आयोग बिना हलफनामे के नोटिस जारी कर दे और उन्हें एसडीएम के दरवाजे पर चक्कर लगाने के लिये विवश कर दे।

मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप संगीन है और ऐसे विषय में बिना हलफनामे के आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है।

चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी की उपस्थिति में ज्ञानेश कुमार ने गांधी के आरोपों पर कहा, सात दिन में हलफनामा दें, नहीं तो देश से माफी मांगे। अन्यथा यही माना जाएगा कि ये आरोप निराधार हैं।

उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार 18 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक को ही वोट देने का अधिकार है तथा मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित किये गये हैं, जिनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। कुमार ने कहा कि कुछ लोग चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख कर मतदाताओं को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ा है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पंजीकरण के साथ बनते हैं। आयोग न तो किसी के पक्ष में हो सकता है और न विपक्ष में। आयोग के लिए सभी समकक्ष

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंजाब केसरी
MON,18 AUGUST 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

विसंगति ठीक करने का SIR एकमात्र तरीका : सीईसी

■ कहा, कई मतदाता सूचियों में नाम होने का अर्थ कई बार बोटिंग नहीं

नई दिल्ली, 17 अगस्त (एजेंसी): मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को स्वीकार किया कि मतदाता सूचियों में विसंगतियां हो सकती हैं और कहा कि इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका एसआईआर है। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति का कई मतदाता सूचियों में नाम होने का यह मतलब नहीं है कि उसने कई बार मतदान भी किया हो।

कुमार ने यह भी कहा कि आयोग पहले ही कई लोगों के एक ही मतदाता पहचान पत्र संख्या वाले तीन लाख से ज्यादा मामलों की पहचान कर उन्हें ठीक कर चुका है, लेकिन एक व्यक्ति के कई जगहों पर मतदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के 'डुप्लिकेट मतदाता' मुद्दे को केवल एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। कुमार ने कहा, 'जमीनी स्तर पर, सभी मतदाता, राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष, बीएलओ पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं और वीडियो गवाही दे रहे हैं।

यह चिंताजनक बात है कि ये प्रयास उनके राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं, या वे भ्रम पैदा करने के लिए इसे अनदेखा कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि सभी हितधारक एसआईआर को सफल बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं।' मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे एक सितंबर से पहले बिहार मसौदा मतदाता सूची में त्रुटियों को उजागर करें।

एसआईआर जल्दबाजी में नहीं

विपक्ष द्वारा बिहार में एसआईआर के समय पर सवाल उठाए जाने पर कुमार ने कहा कि यह एक मिथक है कि एसआईआर जल्दबाजी में किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक चुनाव से पहले मतदाता सूची को सही करना निर्वाचन आयोग का कानूनी कर्तव्य है। कुमार ने कहा कि एसआईआर के बाद बिहार की मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए नामों की सूची उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर डाल दी गई है।

नई दिल्ली : चुनाव आयुक्तों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।

निर्वाचन आयोग नहीं करता दलों में भेदभाव

कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता तथा सतारूढ़ और विपक्षी दल, दोनों ही चुनाव प्राधिकार के लिए समान हैं। उन्होंने कहा, 'निर्वाचन आयोग के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं तथा बूथ स्तर के अधिकारी और एजेंट पारदर्शी तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं।'' कुमार ने कहा, 'निर्वाचन आयोग बिना किसी की राजनीति की परवाह किए सभी वर्गों के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह अडिग रहेगा।'

मशीन रीडएबल सूचियों पर है रोक

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी याद दिलाया कि उच्चतम न्यायालय ने 2019 के एक फैसले में 'मशीन रीडएबल' मतदाता सूचियों को साझा करने पर रोक लगा दी थी क्योंकि ऐसा करने से मतदाताओं की निजता का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा, 'हमें मशीन-रीडएबल मतदाता सूची और खोजे जा सकने वाले प्रारूप में मतदाता सूची के बीच अंतर समझना होगा। आप ईपीआईसी नंबर दर्ज करके निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मतदाता सूची खोज सकते हैं।

क्या माताओं-बहनों के वीडियो साझा करने चाहिए

कुमार ने कहा कि कुछ दिन पहले चुनाव के दौरान 'वोट चोरी' का दावा करने के लिए कई मतदाताओं की तस्वीरें उनकी अनुमति के बिना मीडिया में इस्तेमाल की गईं। उन्होंने पूछा, 'क्या निर्वाचन आयोग को माताओं-बहनों समेत मतदाताओं के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए? केवल मतदाता सूची में नाम वाले लोग ही अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में क्या वोट चोरी की कोई गुंजाइश है?'

पंजाब केसरी
MON,18 AUGUST 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 12

भाजपा को सत्ता से करें बाहर : लालू

राहुल व तेजस्वी से की अपील, बोले-इससे मजबूत होगा हमारा लोकतंत्र

सासाराम, 17 अगस्त (एजेंसी) : राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने रविवार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का आह्वान किया कि वे एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकें। उन्होंने 'I.N.D.I.A.' की 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत के मौके पर आयोजित रैली में लोगों से अपील की कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को जिताएं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'चोरों को हटाइए, भाजपा को भगाइए। 'I.N.D.I.A.' गठबंधन को जिताइए।' उन्होंने कहा कि इस बार किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में आने नहीं देना है।

I.N.D.I.A. की 'वोटर अधिकार यात्रा' के मौके पर रैली को किया संबोधित

यादव ने कहा, 'राहुल जी, तेजस्वी, खरगे जी, आप सब एकजुट हो जाइए और भाजपा को उखाड़ फेंकिए, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके।' भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया, 'भाजपा और चुनाव आयोग ने कई राज्यों में चुनाव चुराने के बाद यही साजिश बिहार में भी की है।' उन्होंने कहा, 'लेकिन ये बिहार है-यहां के लोगों ने साबित कर दिया है कि हमें ये वोट चोरी किसी भी हाल में मंजूर नहीं है।' विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा, 'आज जिस तरह से देश में वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है, वह पूरा देश जान चुका है। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें जो हक दिया, उसे बचाने की लड़ाई लड़नी है।'

सासाराम : मल्लिकार्जुन खरगे व लालू प्रसाद यादव को पानी का गिलास देते राहुल गांधी।

राहुल ने खरगे और लालू को दिए पानी के गिलास, वीडियो वायरल

बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के मौके पर आयोजित जनसभा के दौरान उस वक्त राहुल गांधी का दिल जीतने वाला पहलू देखने को मिला जब भीषण गर्मी के बीच उन्होंने दो दिग्गज नेताओं लालू प्रसाद यादव और मल्लिकार्जुन खरगे को पानी का गिलास दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित हो गया और कई कांग्रेस समर्थकों ने इसे साझा किया। I.N.D.I.A. की वोटर अधिकार यात्रा के मौके पर आयोजित सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव मंच पर अगल-बगल बैठे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने पहले लालू और फिर खरगे को पानी का गिलास दिया। इस जनसभा के दौरान मंच पर निर्दलीय लोकसभा सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी राहुल गांधी के साथ पहली कतार में बैठे थे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को न सिर्फ मंच पर जगह मिली थी, बल्कि उन्होंने सभा को संबोधित किया।

मोदी सरकार का एजेंट बन गया है चुनाव आयोग : खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर रविवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग नरेन्द्र मोदी सरकार का एजेंट बनकर रह गया है। उन्होंने यहां I.N.D.I.A. की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत के मौके पर आयोजित जनसभा में यह दावा भी किया कि देश की आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई योगदान नहीं था लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस संगठन की तारीफ करके स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का अपमान किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए बिहार में गरीबों, मजदूरों, प्रवासियों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के 65 लाख वोट काटे गए हैं और भाजपा-जद (यू) इन वोटों को काटकर सत्ता में आना चाहते हैं।

खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह जनता के वोट, युवाओं की नौकरी और किसानों की एमएसपी चुराते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने 2023 के एक कानून का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मोदी सरकार का एजेंट बन गया है। उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार 2023 में एक कानून लेकर आई। इस कानून के तहत चुनाव आयोग के प्रमुख या सदस्य कोई गड़बड़ करें तो भी उन पर प्राथमिकी या आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।' उन्होंने दावा किया, 'मतलब सरकार ने 2023 में तैयारी की और 2024 में धोखाधड़ी की। इन लोगों ने वोट चोरी की है, इसलिए हमें इन चोरों को हटाना है।'

निर्वाचन आयोग के कंधों पर लोकतंत्र बचाने का दायित्व : अखिलेश

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि वर्तमान में लोकतंत्र को बचाने का ऐतिहासिक दायित्व निर्वाचन आयोग के कंधों पर है और जब आयोग सही रास्ते पर चल पड़ेगा तो करोड़ों भारतवासियों का साथ उनका रक्षा कवच बन जाएगा। यादव ने यहां जारी एक बयान में कहा कि आयोग का एक सही और साहसिक कदम देश की अनंत पीढ़ियों का भविष्य और कल्याण सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने कहा, 'निर्वाचन आयोग को सुधार ही नहीं, आमूलचूल परिवर्तन की अपरिहार्यता है।

आज लोकतंत्र को बचाने का ऐतिहासिक दायित्व उसके कंधों पर है। माना उनके ऊपर कई प्रकार के अवांछित दबाव काम कर रहे हैं लेकिन वो ये न समझे कि वो अकेले हैं।' यादव ने कहा, 'सत्य के मार्ग पर चलनेवालों के साथ जनता और जनविश्वास स्वयं चलने लगता है। सबको अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए।' उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'समाजवादी पार्टी ने वोट की डकैती के 18 हजार शपथ पत्र भारत निर्वाचन आयोग को दिए लेकिन कार्रवाई सिफर रही।'

सासाराम : वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी व तेजस्वी यादव।

पूरी तरह उजागर हो गई है निर्वाचन आयोग की अक्षमता : कांग्रेस

नई दिल्ली : कांग्रेस ने 'वोट चोरी' के अपने आरोपों को लेकर रविवार को निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया के बाद पलटवार करते हुए कहा कि आयोग की न केवल अक्षमता बल्कि पक्षपात भी पूरी तरह से उजागर हो गया है। कांग्रेस ने आयोग के इस दावे को भी हास्यास्पद बताया कि वह सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच कोई अंतर नहीं करता। कांग्रेस के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों के संवाददाता सम्मेलन के तुरंत बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया क्या आयोग उच्चतम न्यायालय के 14 अगस्त के आदेशों को अक्षरशः लागू करेगा। उन्होंने कहा, 'आज राहुल गांधी द्वारा सासाराम से I.N.D.I.A. की मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करने के कुछ ही देर बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने यह कहना शुरू किया कि वे सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच कोई अंतर नहीं करते।' रमेश ने 'एक्स' पर लिखा, 'यह हास्यास्पद है।'

मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों पर जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं: गोपी

त्रिशूर: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस और वामपंथी दलों द्वारा लगाए गए मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों का जवाब देने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है और भारत निर्वाचन आयोग उन्हें इस संबंध में जवाब देगा। गोपी ने कहा कि वह एक मंत्री हैं और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं।

कहा, बखूबी निभा रहा हूं अपनी जिम्मेदारी

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा के नेता ने उन लोगों को 'वानर' भी कहा जिन्होंने उन पर मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। गोपी ने कहा, 'निर्वाचन आयोग इस (आरोपों) पर जवाब देगा। निर्वाचन आयोग को ही जवाब देना चाहिए... मैं एक मंत्री हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा हूं। वरना, जब वे इस मामले को उच्चतम न्यायालय ले जाएंगे तो उन्हें जवाब मिल जाएगा।' उन्होंने कहा कि जिन 'वानरों' ने ये आरोप लगाए हैं, वे भी जवाब पाने के लिए वहां जा सकते हैं। यह पहली बार है जब गोपी ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के सिलसिले में अपने और भाजपा के खिलाफ लगे, मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों का जवाब दिया। सुबह केंद्रीय मंत्री ने कोच्चि राज्य के पूर्व शासक शक्थान थंपुरन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में, जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के अध्यक्ष जोसेफ तजेट ने सुरेश गोपी की वानर संबंधी टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की संस्कृति उन्हें उसी तरह की भाषा में जवाब देने की इजाजत नहीं देती।

चर्चा चुनाव सुधारों की : राजनीतिक अपराधीकरण का पहला कदम

राम निवास बैरवा

चुनाव सुधारों की चर्चा, मुख्य रूप से, क्षेत्रीय पार्टियों के प्रभावी होने के साथ ही शुरू हो गई थी। चुनावी व्यवस्था में बिखरे कांटों को नये कानून बना कर दबाने को ही चुनाव सुधार कहा जाता है। और फिर भी सुधार नहीं हो पा रहा है तो यह चुनावी प्रणाली की असाध्य बीमारी के लक्षण हैं जिनका पता लगाना समय की जरूरत है। वैसे तो राजनीति सत्ता स्वयं में वर्ग संघर्षों की उपज है, लेकिन वर्ग संघर्षों के धीमा हो जाने या शान्ति काल में सत्ताधारी वर्गों के अन्तर्विरोध छिपे रूप में या प्रकटत: षड्यंत्रों में अभिव्यक्त होते हैं। जहां षड्यंत्र किये जाते हैं वहां अपराधिक दुष्टताओं के अलावा कानूनी षड्यंत्रों के भी चक्रव्यूह गढ़े जाते हैं। भारत के चुनाव कानूनों का इस प्रकार की चक्रव्यूह रचनाओं में भरपूर इस्तेमाल किया जाता रहा है।

चुनावी कानूनों के तामझाम की व्याख्या को समझने के लिए, वित्त वर्ष 2012-13 के केंद्रीय बजट भाषण में तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने सर्विस टैक्स की दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा करते हुए कहा था, "मैं दयावान बनने के लिए ही क्रूरता करता हूँ (I have to be Cruel to be kind) तब प्रणव मुखर्जी ने शेक्सपीयर के कथन की दूसरी पंक्ति को नहीं कहा था। पूरा कथन इस प्रकार है- "मैं दयावान बनने के लिए क्रूरता करता हूँ, इस प्रकार खराबियां पीछे रह जाती हैं और बुराई शुरू होती है (I have to be Cruel to be kind, Thus bad begins and worse remains behind)।

भारत में चुनाव कानून बनाने की शुरूआत संविधान लागू होने के तत्काल बाद शुरू कर दी गई थी। इस कड़ी में पहला कानून बनाया गया था "जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, जिसे 12.मई.1950 को बनाया गया था। उस अधिनियम की धारा 16 में मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्यताएं बताते हुए इसी धारा की उपधारा (1) में तीन परिस्थिति गिनाई गई हैं-

जो भारत का नागरिक न हो

जिसकी सक्षम न्यायालय द्वारा दिमागी अस्वस्थता प्रमाणित की गई हो,

जो तत्कालीन भ्रष्टाचारों संबंधी कानून के किसी प्रावधान के अन्तर्गत भ्रष्ट गतिविधियों तथा चुनावों से संबंधित अन्य अपराधों में संलिप्त हो।

12 मई 1950 को बनाये गये उस कानून में छ: महिनों में ही 23.12.1950 से संशोधन करके 'गैरकानूनी' शब्द और जोड़ा गया था- इस प्रकार खण्ड (सी) का पाठ इस प्रकार हो बना दिया गया था, "तत्कालीन भ्रष्टाचार संबंधी कानून के किसी प्रावधान के अंतर्गत "भ्रष्ट और गैर-कानूनी गतिविधियों तथा चुनावों से संबंधित अन्य अपराधों में संलिप्त हो।" इस 'गैर कानूनी' शब्द को 26.12.1960 से हटा दिया गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि अब "गैर कानूनी" गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति अयोग्य नहीं रह गया था।

परन्तु, इस बीच, 1 जुलाई, 1951 से दूसरा पूरक "जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 बनाया गया। उसके भाग 2 के अध्याय तीन में पूरी चुनावी प्रकिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इस अध्याय का मूल शीर्षक था, "संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं" इसकी धारा 7, 8 तथा 10 को 28.08.1956 से संशोधित किया गया, फिर 14.12.1966 से धारा 7, 8, 8-ए, 9, 9-ए, 10, 10-ए तथा 11-ए, 11-बी को पूरा ही पुन: लिखा गया। इसी प्रकार भाग-7 जिसका शीर्षक था-"भ्रष्ट तथा गैर कानूनी गतिविधियां एवं निर्वाचन अपराध" इस में सेभी दूसरे आम चुनावों के ठीक छ: महिने पहले (अधिनियिम सं. 27/1956) 28.08.1956 से 'गैरकाूननी' शब्द हटाकर "भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध" कर दिया गया। इस शीर्षक परिवर्तन के साथ ही धारा 123, 124 तथा धारा 125 को भी दिनांक 28.08.1956 के संशोधन से बदल दिया गया।

इस प्रकार से "गैर-कानूनी गतिविधियों" में संलिप्त लोगों को चुनावों में प्रत्याशी बन कर चुनाव लड़ने की छूट दे दी गई थी, और चुनावों के माध्यम से राजनीति का अपराधीकरण की कानूनी छूट दे दी गई। यहां यह बताना प्रासंगिक नहीं है कि 1956 में कौन प्रधान-मंत्री था और उनके क्या राजनीतिक हित थे, बल्कि यह प्रासंगिक है कि जीत सकने वाले उम्मीदवारों की तब तो 1956 में जरूरत थी ही, आज वह आवश्यकता सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अति-आवश्यक हो गया है, इसीलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी गैर-कानूनी गतिविधियों ममे लिप्त लोगों को चुनावों से दूर करना नहीं चाहती है। चुनावों के राजनीति का अपराधीकरण असाध्य बिमारी बन गया है।

1956 के ये संशोधन करके "गैर कानूनी गतिविधियों" शब्दों को हटाने का क्या कारण रहा था? देश की तत्कालीन परिस्थितियों और जन मानस का विश्लेषण करके उनके अन्तर्संबंधों को देखा जाये तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

1947 के बाद होने वाले 1952 के पहले आम चुनाव थे। उन आम चुनावों में भारत की विशाल ग्रामीण-जनता, किसानों, मजदूरों और दलितों को राजनीतिक भागीदारी के रूप में पहली बार आम चुनावों में मतदान का अवसर मिला था। यह उनके लिए एक अधिकार था, अत: राजनीतिक प्रचार के रूप में कांग्रेस पार्टी के पास चुनावों में चुनावों के लिए भावनात्मक रूप से यह बहुत कुछ था। सबसे पहला, कांग्रेस पार्टी की 1947 के पहले की राजनीतिक गतिविधियों से व्यापकता का लाभ और दूसरा- गांधी जी की हत्या से उनके आदर्शों का व्यापक भावनात्मक लगाव जनता के बीच बना हुआ था। तीसरा-गांधीजी के उत्तराधिकारी के रूप में जवाहर लाल नेहरू के प्रति अटूट विश्वास।

अत: उन चुनावों में केंद्र तथा लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी। तत्कालीन सांसदों, विधायकों से जिन आदर्शों और सुचिताओं की अपेक्षा जनता को थी, वह अगले चुनवों तक डगमगाने लगी थी। साथ ही नेहरू जी को यह विश्वास हो चला था कि चुनावों में जीतने सकने वाले उम्मीदवारों को चुनावों में पार्टीप्रत्याशी बनाना जरूरी था। चूंकि, जीत सकने वाले किसी न किसी गैरकानूनी गतिविधि में संलग्न रहत हैं, अत: गांधीजी के आदर्शों में विश्वास करने वालों को खादी ग्रामाद्योग की जिम्मेदारी देकर, बड़ी जमीनें देकर शान्त कर दिया। लेकिन जीत सकने वाले उम्मीदवारों की रूकावटों को खतम करते हुए 1956 के संशोधन जनप्रतिनिधि कानून में किये गये। चूंकि, अशिक्षित आम जनता के लिए कानूनी संशोधन कोई मायने नहीं रखते। प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बताने के लिए कानूनों में संशोधन किये गये।

ये ही निर्णायक संशोधन थे, जिनसे 'गैरकानूनी' गतिविधियों में शामिल लोगों को चुनाव लड़ने के अयोग्य नहीं माना गया था। 'गैरकानूनी' गतिविधियों में जब संसद और विधानसभाओं में जाने का रास्ता साफ कर दिया गया तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी वह वरदान साबित हुआ। परिणामस्वरूप सभी दलों ने अपने-अपने हितों के लिए अपने-अपने ढंग से सहमति देकर, एक के बाद एक ऐसे कानून बनाये जाते रहे कि उनमें सुधार की बात करना ही निरर्थक है। आज राजनीति का अपराधीकरण उस सीमा तक पहुंच गया है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करने पर उतारू हैं और जिस भी पार्टी के पास सत्ता है वह निश्चित रूप से अपने षड्यंत्रों को कानूनों के आवरण में ढकने में सक्षम है। जैसे- बिहार विधानसभा के चुनावों के पहले बड़ी तादाद में मतदाता सूचियों से नाम काट देना- जातिगत जनगणना का उपक्रम करना आदि। अशिक्षित ग्रामीण भारतीय अब भारतीय हैं या नहीं, यह साबित करने के लिए कागज पैदा करना पड़ेगा नहीं तो वह भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता है।

यह भी एक विडंबना ही है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए सौ खून माफ, परंतु मतदान करने वालों को इस तरह से बांटा जाये, इस तरह से सीमित किया जाये कि अपनी सत्ता को दीर्घायु बनाया जा सके।

-रामनिवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त।

राहुल गांधी ने सासाराम में विशाल सभा के साथ वोटर अधिकार यात्रा शुरु की

बिहार के 20 जिलों की 1300 किलोमीटर की यात्रा के बाद 1 सितम्बर को पटना में बड़ी रैली होगी

- यात्रा से पहले आयोजित सभा को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राजद अध्यक्ष लालू यादव, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सीपीआई (मार्क्सवादी -लेनिनवादी) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य व सुभाषिनी अली सहित कई नेताओं ने संबोधित किया।
- लालू यादव ने वोट चोरी रोकने और वोट चोरों को भगाने के लिये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एकजुट होकर काम करने की सलाह दी।

सासाराम, 17 अगस्त। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार के सासाराम में रविवार को वोटर अधिकार यात्रा शुरु करने से पहले आयोजित विशाल जन समारोह में इंडिया गंठबंधन के प्रमुख दलों के नेताओं ने रैली का पूरी तरह समर्थन करते हुए बिहार की जनता से संविधान बचाने और वोटों के अधिकार की रक्षा के लिए महागठबंधन को वोट देने की अपील की।

रैली में गांधी के अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य और सुभाषिनी अली सहित कई नेताओं ने संबोधित किया और जनता से अपील की कि बिहार को बदलने के लिए वोट चोरी पर रोक लगायें।

गांधी ने कहा कि यह यात्रा बिहार के 20 से ज्यादा जिलों से होते हुए 16 दिनों में 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद एक सितंबर को पटना में समाप्त होगी और उस दिन ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया जायेगा।

सभी नेताओं ने एक स्वर में अपील की कि बिहार को बदलना है और गरीबों, दलितों और पिछड़ों के वोट काटने की साजिश रच कर उनके अधिकार छीनने वालों को बाहर का रास्ता दिखाना है।

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में भी महाराष्ट्र तथा कर्नाटक की तरह वोट चोरी की साजिश हो रही है लेकिन अब वह जनता को जगाने के लिए सड़क पर आ गए हैं और इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा भाजपा की चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में वोटों की चोरी करने की साजिश है और इसके लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) का काम चुनाव आयोग के साथ मिलकर शुरू किया जा चुका है। उनका कहना था कि इस यात्रा से जनता को जागृत कर वह भाजपा के षड्यंत्र पर पानी फेरने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है इसीलिए जब भी चुनाव होते हैं तो भाजपा का षड्यंत्र शुरू हो जाता है। चुनाव अगर विपक्ष जीत रहा है तो इसे रोकने का षड्यंत्र शुरु हो जाता है। चुनाव के सारे अनुमान और चुनाव पूर्व सर्वेक्षण भाजपा के खिलाफ आते हैं लेकिन चुनाव परिणाम अचानक भाजपा की जीत का आता है।

उन्होंने कहा "बिहार की जनता का वोट चोरी नहीं होने देंगे क्योंकि गरीबों के पास सिर्फ वोट है। वोट चोरी चुनाव आयोग करवा रहा है। पहले पता नहीं चलता था कि वोट चोरी हो रही है लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका पर्दाफाश किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बिहार में वोट चोरी करके दलितों पिछड़ों और अन्य सभी कमजोर वर्गों का शोषण किया जा रहा है इसलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है और बिहार की जनता तथा विपक्ष के सभी दलों के नेताओं को एकजुट होकर इसमें शामिल होना चाहिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'चारा चोरी वाले वोट चोरी का फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं'

पटना, 17 अगस्त। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन के द्वारा शुरू किये गये वोटर अधिकार यात्रा के सकारात्मक उद्देश्य पर संदेह जाहिर किया और कहा कि महागठबंधन के नेता, विशेषकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार के लोगों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं।

मंत्री राय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बयान पर तंज कसते हुये कहा कि चारा चोरी करने वाले वोट चोरी का फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैं लालू यादव जी से पूछना चाहता हूं कि चारा चोरी किसने की? वर्दी घोटाला किसने किया? अलकतरा चोरी किसने किया? दूध की चोरी किसने की? उन्होंने कहा कि लालू यादव घोटाले के पहाड़ पर खड़े होकर चोरी का आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिये कि किस तरह आपने विदेशी घुसपैठिये, बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों को वोटर बनाकर लंबे समय तक बिहार में शासन किया है। इसका जवाब दीजिये।

- केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद ने बिहार की वोटर अधिकार यात्रा को जनता को गुमराह करने की साजिश बताया।

सूचि में हेराफेरी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं। उन्होंने कहा कि सूची में त्रुटि संभव है पर "मतदान की चोरी का आरोप संविधान का अपमान है। घर के पते के स्थान पर शून्य दर्ज होने के मामले में उन्होंने कहा, देश में ऐसे बहुत से नागरिक है, जिनके पास घर नहीं है। वे किसी पुल के नीचे, किसी लैंप पोस्ट या बिना पते की जगह पर रहते हैं। वे भारत के नागरिक हैं और उन्हें मतदाता के तौर पर पंजीकरण करवाने का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे लोगों के लिए आयोग की कम्प्यूटर प्रणाली में घर के पते की जगह शून्य दर्ज हो जाता है। कुमार ने कहा कि मलिन बस्तियों या गांव में मकानों पर नंबर नहीं पड़े हैं और उनमें रहने वालों के पते के स्थान पर भी शून्य दर्ज किया जाता है। उन्होंने कहा कि घर के पते के स्थान पर शून्य दर्ज किये जाने को लेकर आपत्ति उठाना गरीबों का अपमान है। आयोग ने बिहार में मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे राज्य की सूची के नये मसौदे में किसी भी कमी में सुधार के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करें और दावे तथा आपत्तियों के लिए इस महीने के अंत तक बचे समय का उपयोग करें।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की सारी त्रुटियों का यही जवाब है कि सभी राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर काम करें। बिहार में अभी सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियों के लिए 15 दिन का समय बाकी है। इस दौरान यदि वे त्रुटियों को दूर कराने में सहयोगी होंगे, तो आयोग उनका शुक्रगुजार होगा।

Give affidavit within 7 days or apologise: CEC to Rahul

No Third Option: Gyanesh On 'Vote Chori' Charge

Bharti.Jain@timesofindia.com

New Delhi: Chief Election Commissioner **Gyanesh Kumar** on Sunday set a seven-day deadline for leader of opposition in LS Rahul Gandhi to either submit a declaration under oath along with proof of electoral roll irregularities alleged by him, or apologise to the nation as his 'vote theft' claims are rendered baseless and invalid.

▶65L names deleted from draft rolls put on site, P 10

"There is no third option," said a combative Kumar while addressing his first press conference as CEC. He was flanked by election commissioners S S Sandhu and Vivek Joshi.

"If one does not point out errors within these timelines and also fails to file an election petition within 45 days to challenge the result, but still tries to mislead the voters with false allegations of 'vote chori', is this not a subversion of the Constitution?" asked Kumar. "A lie, if repeated several times, does not become a truth."

"The voter knows the motive behind such baseless allegations," the CEC said while accusing parties of firing from the Election Commission's shoulder.

▶Related report, P 10

Rahul hits back: 'Law changed, EC colluding with BJP in vote theft'

The Election Commission is helping BJP and "indulging in vote theft in collusion with them", Rahul Gandhi said on Sunday, soon after he along with INDIA bloc parties launched the 'Voter Adhikar Yatra' in Bihar against the special intensive revision of electoral rolls, **reports Ambika Pandit**.

"I want to ask them why did the govt change the law on CCTV footage of election process? Do you know no case can be initiated against the election commissioners. This law was made in 2023," he said.

Congress veteran Jairam Ramesh said on X, "as far as CEC's threats are concerned, all that needs to be said is that the LoP had simply stated facts revealed by EC's own data". **P10**

'List of 65L deleted from Bihar rolls uploaded within 56hrs of SC order'

Bharti.Jain@timesofindia.com

New Delhi: Stating that EC has uploaded the list of 65 lakh voters deleted from Bihar's draft electoral roll within 56 hours of SC's directive, CEC Gyanesh Kumar on Sunday exhorted electors and political parties in the state to file their claims and objections in the remaining 15-day timeframe, saying flagging any errors after Sept 1, shall be pointless.

Justifying its decision to undertake SIR exercise in Bihar, EC said all the political parties had, for the past two decades, been demanding that imperfections in electoral roll be corrected. "Acting on this demand, EC decided to take up SIR, starting with Bihar," he told a press conference here, while adding that the timeline for SIR in other poll-bound states will be announced "at the appropriate time".

Slamming the "vote theft" allegations levelled by opposition parties and their chiefs, EC said the electors, party representatives and booth level officers on the ground are working in a harmonious and transparent manner, endorsing the exercise with their signatures and video testimonials. "It is a matter of concern that endorsements of district presidents and booth level agents of parties are either not reaching their state level and national leadership, or the latter have chosen to overlook these, and are trying to spread misinformation," said Kumar.

"All the political parties have, for past two decades, been seeking that imperfections in poll rolls be corrected. Acting on this, EC decided to take up the SIR exercise, starting with Bihar

GYANESH KUMAR
Chief election commissioner

Clearing the air on timing of SIR, the CEC said that since the annual summary revision was with respect to Jan 1, 2025, April 1 was too early to start the next revision, while Oct 1 would have been too close to the assembly poll due in Bihar in Nov.

As regards allegations of hundreds and thousands of voters being registered on the same address, Kumar said in the absence of proper numbering of houses/addresses by the panchayats/municipalities and also the presence of unauthorised settlements, it has been an accepted norm for EC/BLO to register voters from notional addresses, often carrying 'zero' house number. Electoral roll excerpts shared by EC with **TOI**, of Assam in 1966, Rajasthan in 1980, UP in 1985, show their house number as either missing or as '01'.

Rahul hits back at EC, says it's helping BJP steal votes

'Law Introduced In 2023 To Give Poll Panel Brass Court Immunity'

Ambika.Pandit
@timesofindia.com

Rahul with RJD's Lalu Prasad at 'Voter Adhikar Rally' in Sasaram Sunday

Sasaram: Reacting sharply to Election Commission's press conference on a day he along with INDIA bloc parties launched 'Voter Adhikar Yatra' in Bihar against the SIR exercise, leader of opposition in Lok Sabha and Congress functionary Rahul Gandhi on Sunday alleged that a law was brought in 2023 by BJP govt to ensure that no court can take action against election commissioners as the poll body is "helping them and is indulging in vote theft in collusion with them".

Amid loud sloganeering against "vote chori" and in the presence of RJD chief Lalu Prasad and leader of opposition in Bihar assembly Tejashwi Yadav, Rahul asked the crowd "apka mood kaisa hai" and after the audience settled to listen, he launched a scathing attack on BJP and RSS, accusing them of trying to "wipe-out" the Constitution by stealing elections.

Addressing a public meeting in Aurangabad after launching the yatra in Sasaram, Rahul said, "I want to ask them why did govt change the law on CCTV footage of election process? Do you know that no case can be initiated against election commissioners. In no court in India can there be a case against them. This law was made in 2023. Why was this law made at this time?"

Rahul alleged this law was made as PM Narendra Modi and home minister Amit Shah "want to ensure that no one can take any action against EC as it is helping them and is indulging in 'vote chori' along with them". "EC is asking an affidavit from me but does not ask Anurag Thakur (BJP) for an affidavit when he says the same thing," he alleged.

On X, Rahul said, "EC declared living people as dead, removed from voter list people who had recently voted in LS elections. EC once again refuses to deliver digital, machine-readable voter rolls. Earlier, vote was stolen stealthily, stealthily and now, it is being done openly in the name of SIR."

Congress' Jairam Ramesh on X said "as far as the CEC's threats to Rahul are concerned, all that needs to be said is that the LoP had simply stated facts revealed by EC's own data." He said, "This was the first time this 'new' EC was speaking directly and not planting through sources" and that the presser came "three days after SC rejected every argument made by EC to prevent publication of the 65 lakh deleted voters during SIR".

Poll panel doesn't discriminate between parties, does its job as per statute: CEC

▶ Continued from P 1

EC stands fearlessly with every voter, CEC Gyanesh Kumar said

Explaining the procedure for pointing out errors in electoral rolls, Chief election commissioner (CEC) Gyanesh Kumar said an elector of an assembly constituency (AC) or booth level agents (BLAs) appointed by parties can file claims and objections on the draft voter list with the sub-divisional magistrate (SDM), a state govt employee who is also the electoral registration officer (ERO), or use the two-point appellate process to get corrections made after the final electoral roll is published.

"EC does not discriminate between parties. It simply discharges its duties as enshrined in the Constitution," he added. Kumar reiterated that EC, as required by Article 326 of the Constitution, is committed to enrolling every Indian citizen who is 18 years and above, as voters. "The commission stands fearlessly like a rock with every voter, be he/she poor or rich, elderly or young, or from any caste or religion," said Kumar.

Elaborating on the poll body's insistence on a signed declaration from Rahul, but not using the same yardstick with BJP MP Anurag Thakur after he made similar allegations, the CEC said EC believes in graded response. He further explained that any elector from an AC has the right to complain about exclusion; similarly, BLA can also complain under oath.

"But if the complainant is not a voter in that AC, and is making serious allegations about exclusion of 1.5 lakh voters while calling EC a 'chor', it warrants an escalated response as per Rule 20(3)(b), which requires ERO to administer an oath to the complainant as a witness," he said. "EC cannot act based on a PPT presentation with wrong facts," added Kumar.

Though Thakur had alleged fake voters in constituencies, including Rae Bareli and Wayanad, during 2024 LS polls, he did not cast any aspersions on EC.

Drawing a distinction between voter list errors and actual voting, Kumar said while there may be electors in the voters' list who are dead, permanently shifted or enrolled at multiple places, the commission chose not to delete them by simply using technology and instead required statutory forms to be filled.

With SIR, starting with Bihar, such entries can be identified and weeded out after due house-to-house verification. "But when it comes to voting, one person can only cast one vote," he stressed.

On demand for machine-readable rolls, the CEC said a machine-readable voter list is different from a searchable voter list. The latter, he said, can be searched with EPIC number. As regards machine-readable roll, Supreme Court had in 2019 prohibited it from being shared, citing voters' privacy concerns.

EC BACKS REVISION OF ROLLS IN BIHAR, SAYS OPPN DOING POLITICS OVER IT

Press Trust of India

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The electoral roll revision is aimed at removing all shortcomings in voter lists and it is a matter of grave concern that some parties are spreading misinformation about it and "firing from the Election Commission's shoulder", CEC Gynaesh Kumar said on Sunday as the INDIA bloc parties launched 'Vote Adhikar Yatra' in poll-bound Bihar against alleged "vote-chori".

Addressing a press conference, the Chief Election Commission (CEC) rejected as baseless the allegations of double voting and "vote theft" and asserted that all stakeholders are working to make Special Intensive Revision (SIR) a success in a transparent manner.

With the opposition questioning the timing of the electoral roll revision in Bihar, Kumar said that it is a myth that SIR has been carried out in haste and emphasised that it is the EC's legal duty to correct the voter list before every election.

"It is a matter of grave concern that some parties and their leaders are spreading misinformation on SIR in Bihar... some political parties are firing from the Election Commission's shoulder. The EC exhorts all political parties to file claims and objections on draft electoral rolls in Bihar...15 days are still remaining," the CEC said. →P5

FIRST INDIA

18 August 2025

EC stealing polls in collusion with BJP; nation knows: Rahul

PTI

Sasaram (Bihar)

Embarking on a 1,300 km 'Voter Adhikar Yatra' from here, Congress leader Rahul Gandhi on Sunday accused the Election Commission of "stealing" elections in collusion with the BJP and asserted that the INDIA bloc will not let their "latest conspiracy" to steal Bihar polls through SIR of electoral rolls succeed.

With barely three months left for the Bihar Assembly polls, Gandhi, along with RJD's Tejashwi Yadav and other leaders of Mahagathbandhan -- Vikassheel Insaan Party's Mukesh Sahani and CPI(ML) Liberation general secretary Dipankar Bhattacharya -- launched the yatra, sending a message that the Opposition is united in the state.

Rahul was seen standing in a jeep driven by Yadav and accompanied by other leaders of Mahagathbandhan. In his remarks at the yatra launch event, Gandhi alleged that assembly and Lok Sabha polls were being "stolen" across the country and there was a "conspiracy" in Bihar to do the same through the Special Intensive Revision exercise. He said while he was asked to submit an affidavit after his press conference exposing "vote chori", no such demand was made from BJP leaders who made claims in their presser.

"In the whole country, assembly and Lok Sabha elections are being stolen and their latest conspiracy is to delete and add voters through SIR to steal the elections in Bihar," Gandhi charged.

Congress President Mallikarjun Kharge, LoP in the Lok Sabha Rahul Gandhi and RJD Chief Lalu Prasad Yadav during the 'Voter Adhikar Yatra', in Sasaram on Sunday. PTI

CONSTITUTION UNDER THREAT, PEOPLE'S RIGHTS NOT SAFE AS LONG AS BJP IS IN POWER: KHARGE

Congress president Mallikarjun Kharge on Sunday charged the Election Commission with acting like an "agent" of the "dangerous" Narendra Modi government at the Centre, which posed a "threat" to the Constitution and the people's right to vote. PM Modi's effusive praise of the RSS, the BJP's parent body, in his Independence Day speech drew strong criticism from Congress president Mallikarjun Kharge, who, on Sunday, claimed that the outfit had been "opposed" to freedom from the British.

FIRST INDIA

18 August 2025

CEC Kumar has dismissed Rahul Gandhi's "vote chori" allegations as baseless, reiterating the EC's credibility and transparency. With a stern challenge to provide proof or apologise, the Commission has made it clear that it won't let doubts over the electoral process go unchallenged

EC COUNTERS 'VOTE CHORI' ALLEGATIONS

- Defends electoral rolls, challenges Rahul Gandhi to submit proof or apologise
- Cites privacy concerns of voters for not sharing CCTV footage from polling booths

Agencies
New Delhi

Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar on Sunday launched a strong counter-attack on allegations of "vote chori" (electoral fraud) made by Congress leader Rahul Gandhi. Without naming him directly, the CEC said the "PPT presentation" shared by the Leader of Opposition was based on "wrong analysis" of voter data.

The Chief Election Commissioner also vouched for the sanctity of the electoral process in the largest democracy of the world. P6

DEADLINE ALERT
CEC Kumar appealed to political parties: "All 12 recognised political parties should point out errors before September 1. After that, no complaints will be

WHOLE COUNTRY NOW KNOWS EC 'STEALING' POLLS IN COLLUSION WITH BJP: RAHUL

Congress leader Rahul Gandhi on Sunday claimed the whole country now knows that the Election Commission is "stealing" elections in collusion with the BJP and asserted that the INDIA bloc will not let their "latest conspiracy" to steal Bihar Assembly polls succeed, as he embarked on his 1,300 km 'Voter Adhikar Yatra' in the state from Sasaram. Gandhi alleged that assembly and Lok Sabha polls were being "stolen" across the country and there

LoP in the Lok Sabha Rahul Gandhi with RJD leader Tejashwi Yadav

4 ALLEGATIONS & EC'S RESPONSE

1 HOUSE NUMBER ZERO

Rahul Gandhi's claim: Thousands of voters listed with "house number zero."

EC response:

- Many rural homes don't have house numbers; a notional "0" is used.
- Homeless people, those living under bridges or in unauthorised colonies are also included.
- "Nationality and age 18+ are key factors—not address," said the CEC.

2 DUPLICATE ENTRIES

Rahul Gandhi's claim: Names appear in multiple booths, enabling duplicate voting.

EC response:

- Having same name in two lists doesn't equal voting twice.
- Casting more than one vote is a criminal offence.
- "Electoral rolls and voting are separate subjects, with separate laws and functionaries," said CEC Kumar.

3 22L DEATHS IN 6 MTHS (BIHAR)

Rahul Gandhi's claim: 22 lakh deaths reported in just six months.

EC response:

- The number reflects deaths accumulated over the period of 20 years.
- Last SIR in Bihar in 2003; only summary revisions done since then.
- The SIR involves door-to-door verification, unlike summary revisions.
- "India has 90–100 cr voters. The sanctity of this list is beyond doubt."

4 RUSHED REVISION IN BIHAR

Rahul Gandhi's claim: The SIR is being rushed to favour the ruling party.

EC response:

- Work began June 24 and completed July 20 — not rushed.
- The 2003 SIR in Bihar July (14 July–14 August).
- "It is the EC's legal responsibility to rectify the rolls before elections, not

Myth that Bihar SIR has been done in haste: CEC

Press Trust of India
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The electoral roll revision is aimed at removing all shortcomings in voter lists and it is a matter of grave concern that some parties are spreading misinformation about it and "firing from the Election Commission's shoulder", CEC Gynaesh Kumar said on Sunday as the INDIA bloc parties launched 'Voter Adhikar Yatra' in poll-bound Bihar against alleged "vote-chori".

Addressing a press conference, the Chief Election Commission (CEC) rejected as baseless the allegations of double voting and "vote theft" and asserted that all stakeholders are working to make Special Intensive Revision (SIR) a success in a transparent manner.

With the opposition questioning the timing of the electoral roll revision in Bihar, Kumar said that it is a myth that SIR has been carried out in haste and emphasised that it is the EC's legal duty to correct the voter list before every election.

"It is a matter of grave concern that some parties and their leaders are spreading misinformation on SIR in Bihar... some political parties are firing from the Election Commission's shoulder. The EC exhorts all political parties to file claims and objections on draft electoral rolls in Bihar ... 15 days are still remaining."Doors of the Election Commission are open to everyone, and booth-level officers and agents are working together in a transparent manner," he said.

Kumar said the EC cannot discriminate among political parties, and both ruling and opposition parties are equal before the poll authority.

"It is an insult to the Indian Constitution if election petitions are not filed within 45 days but allegations of vote chori are raised," he said.

Neither the EC nor the voters are scared of "baseless allegations" of double voting and "vote chori", Kumar stressed, adding that the Election Commission will remain steadfast with voters of all classes without bothering about politics being played by some. "More than one crore employees are engaged in the election exercise. Can 'vote chori' happen in such a transparent process?" he questioned.

The comments come as the Opposition stepped up its attack against the poll roll revision in Bihar and on the allegations of 'vote chori' raised by Congress.

Congress leader Rahul Gandhi on Sunday alleged that the whole country now knows that the Election Commission is "stealing" elections in collusion with the BJP and asserted that the INDIA bloc will not let them succeed in their "conspiracy" to steal the Bihar Assembly polls by voter additions and deletions through SIR.

He was addressing a gathering in Sasaram at the launch event of his 1,300 km 'Voter Adhikar Yatra' covering over 20 districts in Bihar.

The CEC said that the latest SIR became necessary in the wake of complaints by many parties and migration of voters within the country. "Knowingly, unknowingly, some people ended up having multiple voter cards due to migration and other issues.... It is a myth that SIR has been carried out in haste. It is EC's legal duty to correct voter lists before every election," he said.

Meanwhile, Congress leader Rahul Gandhi on Sunday claimed the whole country now knew that the Election Commission was "stealing" elections in collusion with the BJP and asserted that the INDIA bloc will not let their "latest conspiracy" succeed.

Addressing the launch event of the yatra, Gandhi said while he was asked to submit an affidavit after his press conference exposing "vote chori", no such demand was made from BJP leaders who made claims in their presser.

DEFENDS S.I.R. EXERCISE, REJECTS ALLEGATIONS OF DISCREPANCIES IN VOTER LIST

Give affidavit in 7 days or apologise to nation: CEC to Rahul as his Bihar yatra hits the road

'Unsuccessful bid to mislead public by using wrong words like vote *chori*'

CEC Gyanesh Kumar (*centre*) with ECs Sukhbir Singh Sandhu (*left*) and Vivek Joshi in New Delhi on Sunday. *Amit Mehra*

DAMINI NATH
NEW DELHI, AUGUST 17

ON THE day Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi launched the "Voter Adhikar Yatra" in poll-bound Bihar accusing the Election Commission (EC) of "vote *chori*", Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar on Sunday asked the Congress leader to either submit his allegations in a sworn affidavit within seven days or apologise to the nation.

In his first press conference since assuming office in February, Kumar termed recent allegations of discrepancies in the electoral roll made by Opposition leaders, particularly Gandhi's press conference on August 7, as "misinformation", saying that there was no evidence.

Gandhi had presented findings of the Congress's six-month study of electoral rolls of Mahadevapura Assembly segment of Bangalore Central Lok

CONTINUED ON PAGE 2

BUSINESS AS USUAL

BY UNNY

EC UPLOADS LIST OF 65L DELETED NAMES

Bihar CEO Sunday published list of 65 lakh names deleted from the draft rolls in first phase of SIR. Names can be searched on Bihar CEO's website using EPIC numbers. The list also has the reasons for deletion. PAGE 7

'SIR latest conspiracy to steal election... will not allow this theft': Rahul targets poll panel

BJP's Anurag Thakur said same things I did... why no affidavit from him?: LoP

ASAD REHMAN
SASARAM, AURANGABAD, AUGUST 17

BEFORE SETTING off on his 16-day, 1,300-km "Voter Adhikar Yatra (Voter Rights March)" from Sasaram in Bihar's Rohtas district on Sunday, Leader of Opposition (LoP) Rahul Gandhi targeted the Election Commission (EC), alleging that its "latest conspiracy" was to "steal the election" in Bihar through the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.

With Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, at a press conference in Delhi, asking the Congress leader to either submit his allegations in a

CONTINUED ON PAGE 2

With RJD leader Tejashwi Yadav at the wheel, Rahul Gandhi in Bihar's Sasaram on Sunday. *PTI*

As voters scramble for one of 11 papers, officials hit on a workaround — family tree as '12th document'

SANTOSH SINGH
MUZAFFARPUR, AUGUST 17

BY JUNE 25, when the first phase of Bihar's Special Intensive Revision (SIR) came to a close, not more than 15-20 per cent of the state's eligible voters had attached any of the EC-mandated 11 documents to establish their identity. As volunteers now scramble to help people get the documents, and with merely two weeks to go before the September 1 deadline, several district administrations have found a way around the problem — the "parivarik suchi" or family tree as an informal "12th document".

According to several Booth Level Officers (BLOs) *The Indian Express* spoke to, electoral officers in all 38 Bihar districts have been reportedly asked to consider the family tree of a voter and establish her/his closest link to the 2003 list.

"We were told at a district subdivision meeting that for those without any of the 11 EC-mandated documents, we can find a way to draw up a family tree linking them to their parents or grandparents in the 2003 electoral roll. Even if a grandparent or

CONTINUED ON PAGE 2

• Rahul slams EC

sworn affidavit within a week or apologise to the nation, Gandhi asked why the poll panel chief had not demanded an affidavit from BJP leader Anurag Thakur. Last Wednesday, Thakur alleged irregularities in voter registration in several Lok Sabha seats held by Opposition leaders and accused them of "vote theft".

"In the whole country, Assembly and Lok Sabha elections are being stolen … Their latest conspiracy is that through SIR in Bihar, by adding new voters and deleting voters, they steal the election. All of us are here to say that we will not let them steal this election. And the people of Bihar will not allow this theft. Because the poor and weak only have their votes," said Gandhi, surrounded by his allies and facing a sea of placards and flags belonging to the Mahagathbandhan parties.

Hitting out at the poll panel, the LoP said, "This is not hidden anymore. The country didn't know how theft was done. But now, after we did the press conference, we made it clear how the EC is stealing elections. We will not allow this theft. Wherever this theft is happening, whether in Bihar, Maharashtra, Assam, or Bengal, we will stop it. The NDA and Narendra Modi run the government with billionaires."

"Wherever there are elections, they (BJP) win. In Maharashtra, all opinion polls said the INDIA bloc would win the elections in the state. During the Lok Sabha polls, our alliance won. Four months later, in the same state, the BJP alliance sweeps and wins elections. We did some inquiry and found that the EC magically gave birth to 1 crore voters between the Lok Sabha and the Assembly elections. Wherever these new voters came, the BJP alliance won," he said.

"Then, we started an inquiry and found that in Karnataka's one Assembly segment in a Lok Sabha seat, and went through all records … We found that in the Vidhan Sabha segment, more than 1 lakh votes were stolen. Because of these votes, the BJP won the Lok Sabha seat in Karnataka. We said this at a press conference and the EC asked me for an affidavit. They didn't ask for an affidavit from anyone else. Some days ago, the BJP people did a press conference but no affidavit was sought from them," he said.

Later in the day, after the yatra halted for the day in Aurangabad, Gandhi said, "Today, they (ECI) held a press conference. I ask them if you made a law on CCTVs. Then, why was it changed by the government? I ask this. Do you know that no case can be lodged against the Election Commissioners? Do you know that no court can file a case against Election Commissioners? Do you know when this law was made? In 2023. Why was it made in 2023? Because Narendra Modi and Amit Shah want no one to take any action against the Election Commission. Because the EC is helping them in stealing votes."

"EC asks me to submit an affidavit, but when Anurag Thakur says the same things that I have said, it does not ask for an affidavit from him," he said.

Opposition workers at the venue frequently broke into bouts of sloganeering to target the poll panel over "vote chori (vote theft)". The ground, which saw thousands in attendance, was awash with different shades of green (RJD flag and the tricolour of the Congress flag) and red (that of the Left and the Vikassheel Insaan Party). While there were loud cheers for all the speakers, from Gandhi to RJD leader Tejashwi Prasad Yadav, the loudest were reserved for RJD president and former CM Lalu Prasad, whom Gandhi thanked for coming despite doctors advising him not to make the trip.

Tejashwi Yadav told the crowd that Prime Minister Modi should not underestimate the people of Bihar. "We may be poor. But we are very sharp, and we will not bow … The Constitution given to us by Dr Ambedkar gave us the right to vote irrespective of how rich or poor. But the BJP people are getting the EC to do its work. They are stealing your votes. People have been declared dead by the EC … This is not vote chori but robbery." Congress president Mallikarjun Kharge accused the EC of acting like an "agent" of the "dangerous" Modi government that, he alleged, poses a "threat" to the right to vote.

Among the other senior Mahagathbandhan leaders who attended the rally were Congress general secretary (organisation) K C Venugopal, VIP chief Mukesh Sahni, CPI(ML) Liberation general secretary Dipankar Bhattacharya, CPI(M) leader Subhashini Ali, and CPI's Sandosh Kumar P.

The march, modelled on Gandhi's Bharat Jodo Yatra and Bharat Jodo Nyay yatras, will pass through 23 districts, covering 50 Assembly segments in 29 Lok Sabha constituencies across several regions of the state before culminating in a mega public meeting in Patna on September 1. On Monday, those on the march are scheduled to travel through Kutumba, Aurangabad, and Deo in Aurangabad district and Guraru in Gaya district.

Every stolen vote is a theft of our voice, identity: Gehlot

Jaipur: Rajasthan Congress on Sunday intensified its campaign alleging "vote chori" by the BJP and Election Commission, with senior leaders changing their social media display pictures to posters with the slogans "Stop Vote Chori" and "Freedom from Vote Theft." Former Rajasthan chief minister Ashok Gehlot, Leader of Opposition Tikaram Jully, former minister Harish Chaudhary and ex-MLA Sanyam Lodha replaced their WhatsApp and X profile pictures in support of the campaign.

Urging party workers and other leaders to follow suit, Gehlot said, "Every stolen vote is a theft of our voice and identity. Rahul Gandhi's fight is to expose the conspiracy of the Election Commission and BJP, and to save democracy." The Congress has held protests across several states, including Rajasthan, and plans to take the issue down to district, block and ward levels.

Congress leader and Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi on Sunday launched a 16-day-long 'Vote Adhikar Yatra' in Sasaram, Bihar. **PTI**